डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 जुलाई, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 जुलाई, 2025

| वर्ष 69 | अंक 03 | भोपाल | 1 जुलाई, 2025 | पृष्ठ 12 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमि. के साथ सहकारी संघ एवं मंडी बोर्ड के बीच हुआ एमओयू

किसानों के उत्पादों को मिलेगा अधिक लाभ : मंत्री श्री सारंग

मध्यप्रदेश की 1578 सोसाइटियों ने ली मेंबरशिप ● मंत्री श्री सारंग और श्री कंषाना की उपस्थिति में हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने सहकारी आंदोलन को मजबूत करने और इसके माध्यम से किसानों को उनकी फसल का और अधिक लाभ उपलब्ध कराने की मंशा से राष्ट्रीय स्तर पर को-ऑपरेटिव सेक्टर में निर्यात की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए नेशनल को-ऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड (एनसीईएल) का गठन किया। इसके माध्यम से किसानों को उनके उत्पाद में अधिक से अधिक लाभ मिल सकेगा। मंत्री श्री सारंग प्रदेश के विभिन्न उत्पादों विशेष रूप से मसालों एवं हैंडीक्राफ्ट उत्पादों के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को भोपाल में राज्य स्तरीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मसालों के निर्यात को संस्थागत रूप से बढ़ावा देने के लिए नेशनल एक्सपोर्ट को-ऑपरेटिव लिमिटेड के साथ मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ और कृषि मंडी बोर्ड के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर किए गये।

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि एनसीईएल के साथ राज्य संघ और मंडी बोर्ड का एमओयू मध्यप्रदेश के किसानों के लिए एक नया प्लेटफार्म उपलब्ध कराएगा। इसके माध्यम से किसान अपने उत्पाद का निर्यात कर सकेंगे। अब किसानों के उत्पादों को उचित दाम तो मिलेगा ही साथ ही सहकारिता आंदोलन को मजबूती मिलेगी। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश की 1578 सोसाइटियों ने एनसीईएल की मेंबरशिप ली है। इससे किसानों के उत्पाद निर्यात होंगे। मध्यप्रदेश किसानों के उत्पाद के लिए भी दुनिया में निर्यातक बनने का कीर्तिमान स्थापित करेगा और मध्यप्रदेश देश में नंबर एक होगा।

सहकारिता कृषि का महत्वपूर्ण अंग -मंत्री श्री कंषाना

किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री एंदल सिंह कंषाना ने सहकारिता को कृषि का महत्वपूर्ण अंग बताया है। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से ही लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और मध्यप्रदेश देश में कृषि क्षेत्र में अग्रणी है। मध्य प्रदेश को सात बार कृषि कृर्मण अवार्ड भी मिला है।

उत्पाद को डिमांड के अनुसार पहुंचाने पर मिलेगा सही दाम- एसीएस श्री वर्णबाल

अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णबाल ने कहा कि एमओयू के जरिये किसानों के उत्पाद को डिमांड के अनुसार पहुंचाने पर सही दाम मिल सकेगा। देश पहले उत्पादों का आयात करता था, अब निर्यात के जरिए इंटरनेशनल मार्केट तक उत्पाद पहुंचाकर सही दाम प्राप्त कर सकेगा। मध्यप्रदेश की धान, मसाले, धनिया, मिर्ची, केले आदि का काफी निर्यात होता है, अब किसानों को इसका सीधा लाभ मिल सकेगा।

एनसीईएल के एमडी श्री अनुपम कौशिक ने कहा कि मध्यप्रदेश के विशिष्ट उत्पादों और किसानों को अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ेंगे, जिसके जरिए उनकी आय में वृद्धि होगी। सहकारिता से समृद्धि और निर्यात से उन्नति की दिशा में हम प्रयासरत है। मध्यप्रदेश सरकार एवं उनके विभिन्न विभाग के सहयोग और समर्थन से हम आगे बढ़ेंगे।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष समारोह के अंतर्गत यह आयोजन एनसीईएल और मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। कार्यशाला में 'मध्यप्रदेश के किसानों को निर्यात के लिये सक्षम बनाना' विषयक संयुक्त उत्पाद संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया।

कार्यशाला में प्रदेश भर से लघु एवं मध्यम स्तर के मिर्च, धनिया, लहसुन आदि मसाला उत्पादक किसान, हस्तशिल्प निर्माता, सहकारी समितियाँ, एफपीओ तथा अन्य उत्पादक समूह ने भाग लिया। विशेषज्ञों द्वारा निर्यात प्रक्रिया, अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों, पैकेजिंग, ब्रांडिंग और बाजार उपलब्धता जैसे विषयों पर सत्र आयोजित किए गये।

कार्यशाला में प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री आलोक कुमार सिंह, प्रबंध संचालक मंडी बोर्ड श्री कुमार पुरूषोत्तम, प्रबंध संचालक राज्य सहकारी संघ श्री ऋतुराज रंजन सहित सहकारिता एवं कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। अंत में सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प ने आभार माना।

तकनीकी सत्र : 'लोकल से

(शेष अगले पृष्ठ पर)

(पिछले पृष्ठ का शेष)

किसानों के उत्पादों को मिलेगा...

ग्लोबल' की ओर - निर्यात, गुणवत्ता और सहकारी सशक्तिकरण पर विशेषज्ञों का गहन मंथन

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के तकनीकी सत्र में विषय विशेषज्ञों, सहकारी प्रतिनिधियों एवं किसानों ने 'लोकल से ग्लोबल' की अवधारणा को साकार रूप देने के लिए निर्यात तत्परता, गुणवत्ता मानक, वैज्ञानिक प्रबंधन, पैकेजिंग तकनीक और सहकारी सशक्तिकरण पर गहन विचार साझा किए।

निर्यात चुनौतियाँ एवं अवसर

तकनीकी विशेषज्ञ प्रेरणा सिंह ने "Export Readiness and Quality Standards" विषय पर प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि भारत में अनेक स्थानीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय मांग रखते हैं, लेकिन अधिकांश उत्पादक निर्यात की तकनीकी आवश्यकताओं, गुणवत्ता मानकों और प्रमाणन प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ हैं।

प्रेरणा सिंह ने कहा कि, "GAP (Good Agricultural Practices) और HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) जैसे वैश्विक मानक अपनाकर किसान अपने उत्पादों को खाद्य सुरक्षा, ट्रेसबिलिटी और गुणवत्ता के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बना सकते हैं। इससे यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के उच्च बाजारों में प्रवेश सुगम होगा।"

उन्होंने उदाहरण स्वरूप बताया कि जैविक धनिया और मिर्ची की वैश्विक मांग तेजी से बढ़ रही है, किन्तु उचित प्रमाणन और क्वालिटी डॉक्युमेंटेशन के अभाव में छोटे किसान उस मांग का लाभ नहीं ले पा रहे।

पोस्ट-हार्वेस्ट प्रबंधन और पैकेजिंग तकनीकें

कार्यक्रम में Post-Harvest Management के व्यावहारिक पक्षों पर भी प्रकाश डाला गया। प्रेरणा सिंह ने कहा कि भारत में उपज के 20-25% हिस्से की गुणवत्ता खराब भंडारण और ग्रेडिंग के अभाव में गिर जाती है। उन्होंने सुझाव दिया कि:

- भंडारण हेतु वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाएं,
- प्राथमिक स्तर पर साफ-सफाई, छंटाई और ग्रेडिंगको बढ़ावा मिले, और अट्रैक्टिव व moisture-proof पैकेजिंगतकनीकों का प्रशिक्षण किसानों व सहकारी समितियों को दिया जाए।

उन्होंने कहा कि अच्छी पैकेजिंग केवल उत्पाद की सुरक्षा ही नहीं करती, बल्कि ब्रांड वैल्यू और बाजार में मूल्य भी बढ़ाती है।

वैश्विक बाजार से जुड़ाव और संभावनाएँ

"Market Linkages and Global Opportunities" विषय पर वक्ता ऋचा शर्मा ने वैश्विक मांग विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए बताया कि आज की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला विश्वसनीयता, गुणवत्ता और निरंतर आपूर्त पिर केंद्रित है।

उन्होंने बताया कि "भारतीय मिर्च, हल्दी, धनिया और लहसुन जैसी मसालों की वैश्विक स्तर पर अत्यधिक मांग है। यदि इन उत्पादों को EU Certification, USDA Organic, Fair Trade जैसे सर्टिफिकेशन के साथ निर्यात किया जाए, तो उनका मूल्य 30-40% तक अधिक हो सकता है।"

एनसीईएल की भूमिका और निर्यात संरचना

एनसीईएल (National Cooperative Export Limited) के प्रबंध निदेशक श्री अनुपम कौशिक ने निर्यात ढांचे की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि एनसीईएल अब सिर्फ एक निर्यात इकाई नहीं, बल्कि किसानों और उत्पादक समूहों को वैश्विक व्यापार से जोड़ने वाला सेतु बन चुका है। उन्होंने विस्तार से बताया :

- सदस्यता प्रक्रिया को सरल किया गया है,
- एग्रीगेशन मॉडल द्वारा उत्पादों का केंद्रीकरण संभव हुआ है,
- और अब Traceability Software व Blockchain आधारित निर्यात ट्रैकिंग प्रणालीपर काम हो रहा है।

उन्होंने कहा "हमारा लक्ष्य है कि छोटे किसानों, एफपीओ और SHGजैसे संगठनों को भी वैश्विक मंच मिले, और उनके उत्पाद प्रतिस्पर्धी मूल्य पर अंतरराष्ट्रीय उपभोक्ताओं तक पहुंचें।"

सहकारी सशक्तिकरण पर पैनल चर्चा

"Cooperative Strengthening and NCEL Engagement" विषय पर एक विशेष पैनल चर्चा आयोजित हुई, जिसमें प्रबंध निदेशक अनुपम कौशिक, प्रबंध संचालक ऋतुराज रंजन, ऋचा शर्मा और प्रेरणा सिंह ने भाग लिया।

पैनल में प्रमुख सुझाव पर जोर दिया गया

- सहकारी समितियाँ अब केवल स्थानीय खरीद केंद्र न रहकर निर्यात-सक्षम बिजनेस यूनिटके रूप में विकसित होनी चाहिए,
- FPOs और PACS के लिए निर्यात आधारित प्रशिक्षण मॉड्यूल बनाए जाएं,
- सहकारी मॉडल के अंतर्गत Shared Logistics, Bulk Certification, Shared Warehousing जैसी सुविधाओं को विकसित किया जाए।
- Cooperative Export Readiness Index तैयार किया जाए, जिससे राज्य की सभी समितियों की निर्यात तैयारी का आकलन किया जा सके।
- सहकारी समितियों के लिए निर्यात संबंधी प्रशिक्षण मॉड्यूल अनिवार्य किए जाएं – जैसे GAP, HACCP, ट्रेसबिलिटी, एक्सपोर्ट डाक्यूमेंटेशन आदि।
- Shared Infrastructure Models (Processing, Cold Storage, Transport, Labelling) विकसित किए जाएं ताकि छोटे उत्पादक लाभान्वित हों।
- समितियों को बाजार अनुकूल उत्पाद चयन और value addition के लिए मार्गदर्शन दिया जाए।

सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने किया सीपीपीपी निवेश विंग का शुभारंभ

मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल सहकारिता क्षेत्र में लाएगा नई क्रांति : मंत्री श्री सारंग

भोपाल : सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने विंध्याचल भवन स्थित सहकारिता आयुक्त कार्यालय में 'सीपीपीपी निवेश प्रोत्साहन विंग' का शुभारंभ किया। विंग में निवेशकों के लिए संपर्क एवं स्वागत कक्ष सहित संवाद एवं विमर्श का स्थान भी बनाया गया है, जहां निवेशक सिंगल विंडो के जरिए संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इस अवसर पर मंत्री श्री सारंग ने कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था में सहकारिता का अहम योगदान है मध्यप्रदेश के सीपीपीपी मॉडल को पूरे देश में सराहना मिली है। इस मॉडल से संपूर्ण सहकारिता जगत में नई क्रांति आयेगी। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी विंग सहकारी समितियों, किसानों और निवेशकों के लिए प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाने के लिये कार्य करेगा। यह विंग निवेश से जुड़ी अनुमतियों, प्रक्रियाओं और मार्गदर्शन के लिए एकीकृत मंच प्रदान करेगा। अब सहकारी बैंकों, समितियों, किसानों और निजी उद्यमियों के बीच एमओयू की प्रक्रिया को सुगम बनाया जाएगा।

विकसित भारत 2047 में सहकारिता की अहम भूमिका

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में सहकारिता क्षेत्र की अहम भूमिका है। 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश में साकार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल पूरे देश में अनुकरणीय पहल के रूप में उभरा है।

मध्यप्रदेश का सीपीपीपी मॉडल सहकारिता क्षेत्र में लाएगा नई क्रांति

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि सहकारी संस्थाओं की उपयोगिता को देखते हुए ग्लोबल इंवेस्टर्स समिट में "सहकारीसार्वजनिकनिजीभागीदारी"सीपीपीपीकीअवधारणाकीसोचकोक्रियान्वित किया गया। इसके तहत रिलायंस, वैद्यनाथ, मैजेस्टिक बासमती राइस जैसी बड़ी कंपनियों के साथ लगभग 2305 करोड़ के 19 एमओयू सहकारी संस्थाओं के साथ निष्पादित किये गये। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी मॉडल किसान, पैक्स और निवेशकों के हित में हैं। इससे किसानों को उनके उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होगा। इससे पैक्स की आर्थिक गतिविधियों में विविधता और विस्तार आएगा निजी निवेशकों को गुणवत्ता युक्त कच्चा माल स्थानीय स्तर पर ही उपलब्ध हो सकेगा।

सीपीपीपी मॉडल को अपनायेगी केंद्र सरकार

मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मध्यप्रदेश के सीपीपीपी मॉडल की प्रशंसा केंद्र सरकार द्वारा भी की गई है और भविष्य में इसे राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया जा सकता है। यह मॉडल सहकारिता जगत में नई क्रांति का आगाज करेगा। उन्होंने कहा कि सीपीपीपी मॉडल से सहकारी संस्थाओं की आय में वृद्धि होगी। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल (सामग्री) सहकारी संस्थाओं के माध्यम से निजी संगठनों को उपलब्ध करवाया जा सकेगा जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

उच्चाधिकारियों और निवेशक प्रतिनिधियों की उपस्थिति

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल, सहकारिता आयुक्त एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प, प्रबंध संचालक विपणन संघ श्री आलोक कुमार सिंह, उप सचिव श्री मनोज सिन्हा सहित रिलाइंस, मैजेस्टिक बासमती राइस, मशरूम वर्ल्ड, प्रतिभा सिंटेक्स कंपनियों के प्रतिनिधि और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। विंग के नोडल अधिकारी श्री अंबरीश वैद्य ने आभार माना।

मध्यप्रदेश को बनाएंगे देश की डेयरी केपिटल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को देश की डेयरी केपिटल बनाएंगे। पशुपालन एवं डेयरी विभाग का नाम पशुपालन, डेयरी और गौपालन विभाग होगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव, मुख्यमंत्री निवास परिसर में राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में प्रदेश भर से आए गौ-पालकों और गौ-शाला संचालकों ने उत्साह से भागीदारी की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौ-शालाओं को 90 करोड़ रुपए की अनुदान राशि अंतरित सिंगल क्लिक से की। इस अवसर पर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तीन हितग्राहियों को प्रतीक स्वरूप ऋण स्वीकृति आदेश भी दिए गए।

मध्यप्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के ठोस प्रयास

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश को देश की दुग्ध राजधानी बनाना है, राज्य शासन द्वारा इसके लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश नदियों का मायका है। पूरा प्रदेश वनों से आच्छादित है। वर्ष 2002-03 तक पशुपालन विभाग का बजट सिर्फ 300 करोड़ था, जो बढ़कर अब 2600 करोड़ हो गया है। किसी समय प्रदेश में फैट मात्रा के अनुसार दूध खरीदने की व्यवस्था लागू की गई थी। राज्य सरकार ने अमृत समान गौ-माता का दूध खरीदने का निर्णय लिया है, ताकि गौ-पालकों तक लाभ पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गाय का दूध सम्पूर्ण आहार है। राज्य में हाईटैक गौशालाएं संचालित हो रही हैं। सरकार का अर्थ ही यह है कि गरीबों के जीवन से कष्टों का नाश हो और सुख का मार्ग प्रशस्त हो। राज्य सरकार ने गौशाला संचालन के लिए अनुदान राशि 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन की गई है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से अनुबंध किया है। प्रदेश का दूध उत्पादन पांच गुना करने का लक्ष्य है। वर्तमान में प्रदेश में साढ़े पांच करोड़ लीटर दूध उत्पादित होता है और इसमें से लगभग आधा घरेलू उपयोग और शेष मार्केट तक पहुंचता है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर प्रदेश में दुग्ध से समृद्धि के लिए नई योजनाएं बना रहे हैं। दुग्ध उत्पादन और संकलन के कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिए समितियों की संख्या भी 9 हजार से बढ़कर 26 हजार करने का संकल्प है।

प्राकृतिक खाद से उत्पादित अनाज का ज्यादा भाव देगी सरकार

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पशुपालन विभाग का नाम बदल कर अब इसे पशुपालन के साथ गोपालन विभाग भी कहा जाएगा। गौ- माता को सम्मान देते हुए इस विभाग के माध्यम से कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जाएंगी। डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना में गाय के पालन के लिए अनुदान दिया जा रहा है। गाय के गोबर से किसान खाद बनाएं, सरकार प्राकृतिक खाद से उत्पादित अनाज का ज्यादा भाव देगी। वर्तमान में इंदौर, देवास, रीवा एवं कुछ अन्य जिलों में गौ-शालाओं के माध्यम से सीएनजी गैस का उत्पादन किया जा रहा है। किसानों को रसायन मुक्त प्राकृतिक और जैविक खाद उपलब्ध हो रही है। बड़ी गौशाला खोलने के लिए राज्य सरकार 125 एकड़ जमीन प्रदान करेगी। वर्तमान बजट में इसके लिए प्रावधान भी किया गया है। अगले तीन साल में गौ-पालन के क्षेत्र में प्रदेश का परिदृश्य बदलेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज 7 गौ-शालाएं पुरस्कृत हुई हैं और गौ सेवी भी सम्मानित हुए हैं। यह भोपाल, दमोह, अनूपपुर, रायसेन, छिंदवाड़ा, हरदा और विदिशा जिलों के हैं। कार्यक्रम में 73 गौशालाओं को पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

गौ-माता के सम्मान के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सड़कों पर घायल होने वाली गौमाता को गौशाला में पहुंचाएंगे। गौ माता अपनी कष्ट निवारण के लिए सड़क पर बैठती है, क्योंकि हमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया है। वर्षाकाल में मच्छरों और कीड़ों से बचाव के लिए गाय और अन्य मवेशी सड़कों तक बैठने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वाहनों के आवागमन से हवा चलने पर उन्हें कष्ट से मुक्ति मिलती है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गायों और अन्य पशुओं के लिए भगवान श्रीकृष्ण समर्पित थे। प्रदेश के हर ब्लॉक में वृंदावन ग्राम बनाए जाएंगे। बच्चों को गाय का दूध मिलेगा तो उन्हें कुपोषण से मुक्ति मिलेगी।

जिनके घर गाय वो गोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जिनके घर गाय है, वे गोपाल है। मुख्यमंत्री निवास आज गौपालकों का निवास हो गया है। जहां गौमाता है, वहीं स्वर्ग है। हमें जन्म भले माता ने दिया है, पहली रोटी का अधिकार गौ-माता का ही है। सनातन संस्कृति में गौमाता का अहम स्थान है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश गौ-पालन से संपन्न बन रहा है। भारत की आत्मा गांवों में बसती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वास्तव में गुजरात में अमूल संस्थान की स्थापना करवाई, हम प्राय: अमूल की प्रगति का श्रेय अन्य लोगों को दे देते हैं। गौ-पालन ऐसा माध्यम है, जो आय प्रदान करता है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने गौशाला संचालकों को अनुदान राशि का अंतरण किया एवं गौसेवा और गौशाला संचालन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली संस्थाओं को वर्ष 2023- 24 के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गौसेवा सम्मान पुरस्कार प्रदान किए।

मध्यप्रदेश में बनेगी स्वाबलम्बी गौशालाएं: पशुपालन राज्य मंत्री श्री पटेल

पशुपालन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री लखन पटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में प्रदेश में निरंतर गौ संरक्षण एवं संवर्धन का कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में 9 अप्रैल 2024 से 29 मार्च 2025 तक गौ संरक्षण वर्ष मनाया गया जिसके अंतर्गत प्रदेश भर में गौ संरक्षण एवं गौ सेवा के कार्य किए गए। सरकार ने प्रदेश में स्वावलंबी गौशालाएं बनाने का निर्णय लिया है। मध्यप्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है। प्रदेश में 30 ऐसे स्थानों को चिन्हित भी कर लिया गया है जहां 5000 से लेकर 25000 तक गोवंश क्षमता वाली स्बावलंबी गौशाला बनाई जाएंगी। ये गौशालाएं हाईटेक होंगी, जहां गायों की देखभाल के लिए सभी आधुनिक सुविधाओं सहित जैविक खाद, सीएनजी गैस उत्पादन आदि के साथ सौर ऊर्जा से बिजली भी बनाई जाएगी। पशुपालन मंत्री ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुना करने में पशुपालन का विशेष स्थान है। गौशालाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पशुओं में नस्ल सुधार आवश्यक है। पशुपालन के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। सरकार ने कामधेनु योजना में 200 गोवंश रखने पर 25 प्रतिशत अनुदान देने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार गौ सेवा के क्षेत्र में गोपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए संस्थागत एवं व्यक्तिगत पुरस्कार दे रही है। वरिष्ठ सांसद श्री वी.डी. शर्मा ने कहा कि गौपालन और गौसेवा मुख्यमंत्री डॉ. यादव के जीवन का हिस्सा है। उन्होंने प्रदेश को पशुपालन में अग्रणी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह प्रदेश में इस क्षेत्र का ऐतिहासिक सम्मेलन है। राज्य सरकार ने नेशनल डेयरी विकास बोर्ड के साथ समझौता किया है। कामधेनु योजना से किसानों को गौपालन और डेयरी शुरू करने का अवसर मिलेगा। गौपालन से कृषि क्षेत्र ही नहीं सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र को मजबूती मिलेगी।

VAMNICOM स्टार्टअप Mettarev ने सहकारी बैंकों के लिए AI-संचालित लेंडिंग टूल लॉन्च किया Mettarev ने NABARD, NAFCUB और NUCFDC के साथ मिलाया हाथ

मुंबई, मुंबई में आयोजित "भारत सहकारी बैंकिंग शिखर सम्मेलन 2025" में भारत के सहकारी क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया, जब Mettarev Systems ने अपना AI-आधारित बैंक स्टेटमेंट एनालिसिस (BSA) प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

यह स्टार्टअप VAMNICOM (वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान), पुणे के Incubation Centre में इनक्यूबेट किया गया है। Mettarev ने एक ऐसा क्लाउड-बेस्ड इंटेलिजेंट प्लेटफॉर्म विकसित किया है, जो सहकारी बैंकों को ऋण मूल्यांकन (क्रेडिट असेसमेंट) आसान, तेज और अधिक विश्वसनीय बनाने में मदद करता है। इससे बैंकों के कर्मचारियों का समय भी बचेगा और धोखाधड़ी की पहचान में भी सहायता मिलेगी।

यह प्लेटफॉर्म AI (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) और मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग कर ब्याजदाता (borrower) के डेटा का विश्लेषण करता है, और अनौपचारिक आय स्रोतों को भी समझकर वित्तीय समावेशन (financial inclusion) को बढ़ावा देता है। पारंपरिक बैंकिंग मॉडल जो ऐसे आय स्रोतों को पकड़ नहीं पाते, उनके मुकाबले यह एक बेहतर विकल्प बनकर उभरा है।

VAMNICOM Incubation Centre, जिसे जुलाई 2023 में पुणे में शुरू किया गया था, सहकार से समृद्धि विजन के तहत केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के नेतृत्व में चल रही पहल का एक भाग है। इस केंद्र ने अब तक 40 से अधिक स्टार्टअप्स और सहकारी संस्थाओं को सहयोग दिया है और पूरे भारत में वर्कशॉप आयोजित की हैं। यह केंद्र PACS, SHGs, और शहरी सहकारी बैंकों के साथ मिलकर काम कर रहा है।इस प्रयास में NABARD, NAFCUB और NUCFDC जैसे प्रमुख संस्थानों का सहयोग है।

डॉ. महेश कदम (सीओओ, Incubation Centre) ने बताया कि "Mettarev का राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च केवल एक स्टार्टअप की सफलता नहीं है, बल्कि हमारे इनक्यूबेशन मॉडल की सफलता का प्रमाण है।" उन्होंने यह भी कहा कि आने वाले समय में भारत का पहला "Cooperative Startup Registry", विशेष नवाचार प्रयोगशालाएं (Innovation Labs) और अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों (जैसे केन्या, जापान और जर्मनी के सहकारी संस्थाओं के साथ) की योजना है।

Mettarev Systems ने एक AI आधारित टूल लॉन्च किया है जो सहकारी बैंकों में डिजिटल लेंडिंग को आसान बनाएगा। यह टूल बैंक स्टेटमेंट का विश्लेषण कर ऋण निर्णय प्रक्रिया को तेज करता है। VAMNICOM Incubation Centre, पुणे द्वारा यह स्टार्टअप इनक्यूबेट किया गया है।

यह पहल "सहकार से समृद्धि" मिशन के अंतर्गत है। NABARD, NAFCUB और NUCFDC इसके मुख्य सहयोगी हैं।भविष्य में भारत का पहला Cooperative Startup Registry, नवाचार प्रयोगशालाएं और वैश्विक साझेदारियां भी प्रस्तावित हैं।

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शिवपुरी (म0प्र0)
कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)
बैलेंस शीट पत्रक वर्षान्त 31 मार्च 2025 की स्थिति पर

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2024		विवरण देनदारियां		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2025
185,807,895.54	1	अंशपूंजी		**685,832,668.54**
500,000,000.00		(अ) अधिकृत अंशपूंजी	500,000,000.00	
		(ब) अभिदत्त अंशपूंजी		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		नाम मात्र के सदस्यों से अंश में		
		(स) प्रदत्त अंशपूंजी		
		अंशो में प्रति अंश रूपय		
		जिसमे से .....बकाया काल्स के कम करने पर		
		नाम मात्र के सदस्यों से अंश में		
		उक्त तीन मे से धारित		
44,463,540.00		1-शासन द्वारा	544,463,540.00	
140,285,470.54		2-समितियों द्वारा	140,310,243.54	
1,058,885.00		3-व्यक्तिगत नाम मात्र सदस्यों द्वारा	1,058,885.00	
1,378,415,593.62	2	आरक्षित निधि एवं अन्य रिजर्व :-		**1,876,778,944.20**
28,381,167.48		रक्षित कोष	28,381,167.48	
17,572,897.10		कृषि साख स्था. निधि	17,572,897.10	
42,949,212.90		भवन निधि	42,949,212.90	
6,621,375.72		वाहन निधि	6,621,375.72	
1,182,578.72		प्रशिक्षण निधि	1,182,578.72	
2,949,636.59		सहकारी विकास निधि	2,949,636.59	
6,759,479.35		अंश विमोचन रिजर्व	6,759,479.35	
115,149,000.00		रिवेल्यूवेशन फिक्स असेट फण्ड	115,149,000.00	
10,119,500.00		विनियोग अस्थिरता संचय	10,119,500.00	
-		विशेष डूबन्त संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	-	
-		संदिग्ध एवं डूबंत ग्रामीण क्षेत्र	-	
994,053,870.33		डूबन्त एवं संदिग्ध निधि हेतु प्रावधान	1,551,011,948.30	
479,442.60		स्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	34,483.67	
69,903,717.95		सबस्टेन्डर्ड असेस्टस हेतु प्रावधान	11,753,949.49	
67,233.25		लाभांश समीकरण निधि हेतु प्रावधान	67,233.25	
60,904.00		विनियोजित निधियां हेतु प्रावधान	60,904.00	

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2024		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2025	
		सिलक एवं बैंक बैलेस		
4,784,209.00	1	नगद रोकड़ तिजोरी में तथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, स्टेट बैंक, सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी बैंक		**4,947,317.00**
159,594,167.80	2	सिलक अन्य बैंकों मे		**180,239,131.84**
		1-चालू अमानत		
(5,519,774.16)		अ-भारतीय स्टेट बैंक	15,742,181.91	
159,163,898.73		ब-अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक	140,122,545.64	
5,950,043.23		स-म0 प्र0 राज्य सहा बैंक	24,374,404.29	
44,928,697.99		2-मुद्दती अमानत		**547,719,461.99**
5,019,699.00		अ-म0 प्र0 राज्य सहक बैंक	505,019,699.00	
29,698,008.00		ब-रक्षित निधि शीर्ष बैंक	31,851,114.00	
1,000,000.00		स-भारतीय स्टेट बैंक	1,000,000.00	
0.00		द-अन्य सावधि जमा	0.00	
9,210,990.99		इ-सेन्ट्रल बैंक	9,848,648.99	
	3	मांग और अल्प सुचना पर प्रतिदेय राशि		
628,401,000.00	4	विनियोग		**628,400,000.00**
584,000,000.00		1-केन्द्रीय एवं राज्य शासन की प्रतिभतियो	584,000,000.00	
-		2-अमानती प्रतिभूतियो मे	-	
44,401,000.00		3-सहकारी संस्थाओ के अंशो मे	44,400,000.00	
	5	ऋण एवं अग्रिम		2,739,925,050.71
2,804,586,265.97		अ-अल्पावधि ऋण, नगदी साख, अधिविकर्ष तथा विलो मे	2,739,925,050.71	
		1-शासकीय प्रतिभूतियों		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
		5-अवमानक संदिग्ध डूबन्त ऋण		
113,878,537.23		ब-मध्यकालीन	113,364,096.61	113,364,096.61
		1-इसमे से शासकीय प्रतिभूतियों पर		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2024		विवरण देनदारियां		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2025
31,806,357.01		कर्मचारी उपादान	31,806,357.01	
16,825.64		सामान्य हितनिधि	16,825.64	
1,997.00		धर्मार्थ निधि	1,997.00	
807.00		कर्मचारी हितनिधि	807.00	
28,967.38		वोनस रिजर्व हेतु प्रावधान	28,967.38	
-		अन्य निधियां हेतु प्रावधान	-	
-		केपीटल रिजर्व हेतु प्रावधान	-	
50,237,000.00		अन्य प्रावधान	50,237,000.00	
73,623.60		केपीटल रिजर्व अन्य	73,623.60	
3,007,294,833.87	3	अमानते :		**3,058,194,735.35**
1,019,779,627.64		(अ) मुद्दती अमानते	**1,035,953,050.64**	
909,009,748.94		1-व्यक्तिगत अमानते	926,868,608.18	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक		
110,769,878.70		3-अन्य सहकारी समितियां	109,084,442.46	
1,915,907,924.40		(ब) बचत अमानते	**1,946,559,612.72**	
1,636,150,802.47		1-व्यक्तिगत अमानते	1,619,482,887.38	
--		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	
279,757,121.93		3-अन्य सहकारी समितियां	327,076,725.34	
71,607,281.83		(स) चालू अमानते	**75,682,071.99**	
29,839,831.05		1-व्यक्तिगत अमानते	30,312,421.55	
-		2-केन्द्रीय सहकारी बैंक	-	
41,767,450.78		3-अन्य सहकारी समितियां	45,369,650.44	
-		(द) आहूत एवं अल्पकालीन अमानते		
642,892,750.00	4	उधार		**642,892,750.00**
		भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, राज्य सहकारी बैंक		
639,000,000.00		(अ) अल्पकालीन ऋण नगद साख, अधिविकर्ष तथा बिलो मे इनमे से अन्य ठोस प्रतिभूति पर	639,000,000.00	
3,892,750.00		(आ) मध्यम अवधि ऋण इसमे शासन प्रतिभूतियो पर , इनमे से अन्य ठोस	3,892,750.00	
-		(इ) दीर्घकालीन	-	
13,229,270.00	5	देने योग्य बिल :		**13,229,270.00**
(260,560,819.95)	6	शाखाओ का जमाखर्चः		**(248,444,383.65)**
228,660,931.06	7	कालातीत ब्याज रिजर्व		**228,660,931.06**
80,595,186.46	8	ब्याज देय		**82,414,396.83**
(912,130,479.48)	9	अन्य देनदारियां		**(1,512,107,542.50)**
15,299,541.03		अ-सस्पेंश		**15,306,373.03**
(927,430,020.51)		ब-विविध देनदारियां		**(1,527,413,915.53)**

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2024		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2025	
1,914,074.00		स-दीर्घावधि	1,853,853.00	1,853,853.00
		1-इसमे से शासकीय प्रतिभूतियों पर		
		2-अन्य ठोस प्रतिभूतियो पर		
		3-व्यक्तिगत ऋण वांकी		
		4-कालातीत वांकी		
134,792,651.68	6	व्याज लेना वांकी	**133,237,158.54**	**133,237,158.54**
		1-कालातीत ऋणो पर		
		2-चालू ऋणो पर		
		3-ऋण राहत शासन से		
1,577,769.00	7	बिल्स रिसीवएवल एज पर कान्द्रा	**1,577,769.00**	**1,577,769.00**
-	8	शाखा समायोजन	-	
193,393.44	9	भवन		**174,054.44**
1,048,867.56		1-पुस्तक मूल्य	1,048,867.56	
855,474.12		2-कम किया अवक्षयण	874,813.12	
1,405,695.22	10	साज सज्जा		**1,265,125.22**
5,593,979.58		1-पुस्तक मूल्य	5,593,979.58	
4,188,284.36		2-कम किया अवक्षयण	4,328,854.36	
790,120.11	11	कम्प्यूटर		**474,072.11**
5,659,318.50		1-पुस्तक मूल्य	5,659,318.50	
4,869,198.39		2-कम किया अवक्षयण	5,185,246.39	
76,444.10	12	ऑफिस इक्यूपमेंट		**68,800.10**
204,476.24		1-पुस्तक मूल्य	204,476.24	
128,032.14		2-कम किया अवक्षयण	135,676.14	
1,058,354.76	13	वाहन		**899,601.76**
2,631,387.00		1-पुस्तक मूल्य	2,631,387.00	
1,573,032.24		2-कम किया अवक्षयण	1,731,785.24	
115,149,000.00	14	भूमि		**115,149,000.00**
351,074,780.82	15	अन्य लेनदारियां		**358,157,277.51**
1,954.00		1-अनाज अग्रिम स्टाफ	1,954.00	
55,111.00		2-वेतन / प्रवास अग्रिम	55,111.00	
550.00		3-त्यौहार अग्रिम	550.00	
1,646,421.22		4-टीडीएस	1,760,668.22	
-		5-अग्रिम आयकर	-	

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2024	विवरण देनदारियां		इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2025
72,796,749.08	1-सण्ड्रीक्रेडिटर्स	72,237,355.24	
(2,120,904.52)	2-फुटकर देनदारियां	93,594.48	
513,943.00	3-अंकेक्षण शुल्क	510,266.00	
9,621,807.58	4- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के देय	8,493,698.58	
21,227,259.57	5- लैव्ही	20,988,717.57	
4,065,527.56	6- कैश केडिट खाद	4,037,220.46	
352,135.45	7- कैश केडिट विपणन	352,135.45	
386,425.85	8- म्यादी अमा० के तारण पर ऋण	470,719.85	
(1,367.50)	9-शासकीय ऋण ज्वाइंट फार्मिंग	(1,367.50)	
168,510.00	10-वोनस देय	168,510.00	
23,293.75	11-वेतन देय	23,293.75	
40,055.81	12-प्रोत्साहन राशि	40,055.81	
(29,294,182.77)	13-संवर्ग निधि	(31,435,620.77)	
913,016.82	14-भविष्य निधि कर्मचारी	932,573.82	
19,817.00	15-बचत बैंक गारंटी	19,817.00	
352,335.25	16-परिवार कल्याण कोष	374,167.25	
(22,078.25)	17-समूह बीमा	(25,415.25)	
42,550.00	18-एलआईसी	64,781.00	
193,237,304.06	19-फर्टीलाइजर सेल्स कलेक्शन	193,237,304.06	
2,461,290.00	20-टीडीएस पेविल	2,714,162.00	
(28.64)	22-जीएसटी पबिल	70,261.36	
2,897,981.00	23-सर्विस टेक्स	3,590,942.00	
936,309,035.22	24-अन्य दायित्व	1,100,808,881.77	
(156,263,480.54)	25-नेफ्ट अन्तर	(156,152,938.11)	
-	26-छात्रवृति	-	
(1,985,157,015.29)	27-लाभ/हानि	**(2,749,027,031.35)**	
4,364,205,161.12		-	**4,827,451,769.83**

हस्ता/-
प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ता/-
प्रशासक/कलेक्टर

दिनांक : 18.06.2025
स्थान : ग्वालियर

अतुल कुमार एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 001982C
हस्ता/-
सीए नेहा गर्ग
पार्टनर
मैं.नं. 415128
UDIN : 25415128BMGXYP3668

गत वर्षान्त पर शेष 31.03.2024		विवरण लेनदारियां (सम्पत्ति एवं आस्तियां)	इस वर्षान्त पर शेष 31.03.2025	
6,577,159.30		6-जीएसटी इनपुट	8,561,624.30	
515,378.07		8-लेखन सामग्री	515,478.07	
26,307.33		9-पुस्तकालय	26,307.33	
967,106.45		10-फार्स एवं पंजियां	967,106.45	
722,475.00		11- Clearing house	722,475.00	
2,386,148.00		12-संडीडेटर्स	2,394,708.07	
9,990,682.17		13-अन्य	9,990,682.17	
29,111,421.30		14-एल आई सील टस्टी फण्ड	30,418,253.30	
-		15-लाभांश प्राप्य एपेक्स बैंक	-	
473,250.00		16-प्रीमियम परिशोधन	473,250.00	
16,420,730.28		17-उपार्जित ब्याज	16,431,842.58	
2,969,203.64		18-राज्य शासन डीएमआर राशि प्राप्य	2,969,203.64	
2,809,506.00		19-केडर फण्ड वेतन समिति प्रबंधक	2,809,506.00	
7,060,130.51		20-केडर फण्ड वसूली योग्य	6,700,042.51	
1,617.32		21-लेव्ही पूल फण्ड	1,617.32	
567,969.00		22-शीर्ष बैंक से लेना शेष	567,969.00	
296,603.10		23-जवाहर रोजगार योजना	296,603.10	
11,502.50		24-संयुक्त ऋण ज्वाइंट फार्मिंग	11,502.50	
9,637,284.33		25 अन्य सम्पत्ति	12,501,997.37	
3.34		26-सिक्योरिटी सेटलमेंट	3.34	
72,693.00		27-अन्य व्यवसायिक सम्पत्ति	72,693.00	
13,574,376.00		28-शासन से मूल लेना	13,574,376.00	
7,230,808.00		29-शासन से ब्याज लेना	7,230,808.00	
237,948,389.96		30-पेक्स से लेना	239,100,945.24	
4,364,205,161.12				**4,827,451,769.83**

हस्ता/-
प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ता/-
प्रशासक/कलेक्टर

दिनांक : 18.06.2025
स्थान : ग्वालियर

अतुल कुमार एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 001982C
हस्ता/-
सीए नेहा गर्ग
पार्टनर
मैं.नं. 415128
UDIN : 25415128BMGXYP3668

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शिवपुरी (म०प्र०)
कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)
लाभ हानि पत्रक वर्ष 2024-25

गत वर्षान्त पर शेष 31-03-2024			इस वर्षान्त पर शेष 31-03-2025
		अन्य	
83,910,299.79	1	ब्याज एवं छट	67,635,436.88
27,111.67	2	कमीशन, विनिमय एवं दलाली	33,992.90
-	3	सब्सिडी तथा अनुदान	-
-	4	गैर बैंकिग आस्तियों से हुई आय तथा ऐसी आस्तियों की बिक्री अथवा लेनदेन से हुआ लाभ	-
5,480,752.42		अन्य प्राप्तियां	5,570,489.97
89,418,163.88		**योग :**	**73,239,919.75**

हस्ता/-
प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ता/-
प्रशासक/कलेक्टर

दिनांक : 18.06.2025
स्थान : ग्वालियर

अतुल कुमार एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 001982C
हस्ता/-
सीए नेहा गर्ग
पार्टनर
मे.नं. 415128
UDIN : 25415128BMGXYP3668

कार्यालय जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या० शिवपुरी (म०प्र०)
कोर्ट रोड शिवपुरी (म.प्र.)
लाभ हानि पत्रक वर्ष 2024-25

गत वर्षान्त पर शेष 31-03-2024			गत वर्षान्त पर शेष 31-03-2025
		व्यय	
142,844,412.66	1	ब्याज दिया अमानत व ऋण पर	302,861,915.04
35,986,222.00	2	वेतन व भत्ते एवं भविष्य निधि	19,400,223.90
-	3	संचालक मण्डल एवं स्थानीय समितियों के सदस्यों का शुल्क एवं भत्ते	-
1,021,702.93	4	किराया, शुल्क, बीमा, बिजली आदि	1,325,303.00
584,140.00	5	विधि व्यय	478,500.00
-	6	आयकर	-
2,033,145.12	7	th,lVh isM	-
658,596.00	8	डाक, दूरलेख एवं दूरभाष	27,750.00
1,576,799.00	9	अंकेक्षण शुल्क	875,329.00
596,651.00	10	संपत्ति पर अवक्षयण एवं दुरूस्ती	642,354.00
204,345.70	11	लेखन सामग्री छपाई तथा विज्ञापन	173,382.23
91,957,301.09	12	मानक संदिग्ध एवं डूबत ऋण हेतु प्रावधान	(56,544,813.39)
357,269,728.54	13	कालातीत ब्याज हेतु प्रावधान	556,958,077.97
9,622,308.56	14	अन्य व्यय	10,911,914.06
-	15	ग्रेच्यूटी बैंक कर्मचारी	-
(554,937,188.72)	16	लाभ जो बैलेन्सशीट में ले जाया गया	(763,870,016.06)
89,418,163.88		**योग :**	**73,239,919.75**

हस्ता/-
प्रभारी प्रबंधक (लेखा)

हस्ता/-
मुख्य कार्यपालन अधिकारी

हस्ता/-
प्रशासक/कलेक्टर

दिनांक : 18.06.2025
स्थान : ग्वालियर

अतुल कुमार एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फर्म रजि नं 001982C
हस्ता/-
सीए नेहा गर्ग
पार्टनर
मे.नं. 415128
UDIN : 25415128BMGXYP3668

JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MYDT. SEHORE (M.P.)
BALANCE SHEET FOR THE YEAR ENDED
BALANCE SHEET OF JILA SAHAKARI KENDRIYA BANK MDT. SEHORE (M.P.) AS ON 31 MARCH 2025

	Particulars		
		31-03-2024	31-03-2025
	Capital and liabilities		
1	Capital	1192113389.00	1192113495.00
2	Reserves, Surplus & Provision	1395864281.07	1531516597.69
3	Deposits	7791410585.69	8792266863.36
4	Borrowings	7220174284.00	7751977568.00
5	Other liabilities	971032913.53	909503542.04
6	Accumulated P/L	133285265.20	139122810.63
7	Net Profit & Loss	51990910.43	9464128.49
	TOTAL	**18755871628.92**	**20325965005.21**
	ASSETS		
8	Cash in hand	122643650.00	246986954.01
9	Balances with banks	628927174.81	976009580.18
10	Investments	2627966778.50	2773768143.50
11	Advances	13907721777.98	14655367537.74
12	Fixed assets	65269859.52	61013696.69
13	Other assets	1403342388.11	1612819093.09
	TOTAL	**18755871628.92**	**20325965005.21**

मेसर्स आर.सी.बहेती एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
रंजन बहेती
फर्म रजिस्टेशन नं. 400993

कलेक्टर एंव प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक
मर्यादित सीहोर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक
मर्यादित सीहोर

निर्गमित किया
संयुक्त आयुक्त सहकारिता
सहकारी संस्थाऐ
भोपाल संभाग भोपाल
26/06/2025

Profit and Loss Account for the Year Ended 31st March 2025

	Particulars	31-03-2024	31-03-2025
	1. Income		
	Interest earned	1294126074.93	**1369487438.49**
	Other income	14689254.13	16646226.54
	TOTAL	**1308815329.06**	**1386133665.03**
	2. Expenditure		
	Interest expended	953810186.44	996369301.27
	Operating expenses	303014232.19	278485169.27
	Provisions and contingencies	0.00	101815066.00
	TOTAL	**1256824418.63**	**1376669536.54**
	3. Profit/loss		
	Net profit/loss(-) for the year	51990910.43	9464128.49
	TOTAL	**1308815329.06**	**1386133665.03**

मेसर्स आर.सी.बहेती एण्ड कम्पनी
सनदी लेखापाल
रंजन बहेती
फर्म रजिस्टेशन नं. 400993

कलेक्टर एंव प्रशासक
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक
मर्यादित सीहोर

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला सहकारी केन्द्रीय बैक
मर्यादित सीहोर

निर्गमित किया
संयुक्त आयुक्त सहकारिता
सहकारी संस्थाऐ
भोपाल संभाग भोपाल
26/06/2025

R. C. BAHETI & CO.
Chartered Accountants
HEAD OFFICE
24, Zone - II, M. P. Nagar, Near Som Distilleries
Bhopal - 462011
Ph. 0755 - 4908690 MOB. 09826282060
Email - rameshchandrabaheti@yahoo.com
ranjanbaheti@gmail.com

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य,

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादीत, सीहोर (म.प्र.)

वित्तीय विवरण पर रिपोर्ट (Report on Financial Statements):-

हमने जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादीत, सीहोर द्वारा दिए गए वित्तीय विवरण पत्रों का लेखा परीक्षण किया है, जिसमें उनका मुख्य कार्यालय एवं 27 शाखाएं शामिल है, जिनमें 31-03-2025 का तुलना पत्र, लाभ और हानि खाता और अन्य स्पष्टीकरण संबंधी जानकारी का सारांश शामिल है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व (Management's Responsibility for the Financial Statements):-

मध्य प्रदेश राज्य सहकारी समिति अधिनियम 1960 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अनुसार इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन जिम्मेदार है, जो वित्तीय स्थिति की सही और निष्पक्ष राय देता है। वित्तीय विवरण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानकों सहित एवं सामान्य लेखा परीक्षा मानदंडों के अंतर्गत, बनाई गयी है। इस जिम्मेदारी में वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुतिकरण से प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की रचना, कार्यानवयन और रखरखाव शामिल हैं, जो वित्तीय विवरण पर सत्य और निष्पक्ष राम को और उनके वस्तुगत त्रुटियों से मुक्तता को दर्शाते है।।

लेखा परीक्षक का दायित्व:- (Auditor's Responsibility)

हमारा दायित्व हमारे अंकेक्षण के आधार पर इन वित्तीय आंकड़ों पर राय व्यक्त करना है। हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के द्वारा जारी किए गए अंकेक्षण के मानकों के अनुसार लेखापरीक्षण किया है। उन मानकों के अंतर्गत हमें यह आवश्यक है कि हम नैतिक नियमों का पालन करते हुए, लेखा परीक्षण की योजना और निष्पादन कर, उचित आश्वासन प्राप्त करते हैं कि वित्तीय विवरण उल्लेखनीय / वस्तुगत त्रुटियों से मुक्त है या नहीं।

अंकेक्षण में वित्तीय वक्तव्यों में राशि और प्रकटीकरण के बारे में साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं शामिल हैं। चयनित प्रक्रियाएं अंकेक्षक के विवेक पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण की त्रुटियों के जोखिम के आकलन शामिल हैं जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो। उन जोखिम का मूल्यांकन करने में, अंक उन आतंरिक नियंत्रणों का ध्यान रखताहै जो वित्तीय विवरणों की रचना और प्रस्तुति में प्रासंगिक है, जिससे वह उन अंकेक्षण प्रक्रिया की रचना कर पाए जो उन परिस्थितियों में उपयुक्त है न कि इकाई के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर कोई सय वाक्त करने के उद्देश्य से एक लेखापरीक्षा में लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन के अनुमानों के मूल्यांकन के साथ-साथ वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति का मूल्यांकन करने का कार्य भी शामिल है।।

हम मानते है कि हमारा अंकेक्षण साध्य आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और अप्रासंगिक है। हमारा विश्वास है की हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किये है, वह हमारी लेखा परीक्षा राम प्रस्तुत करने के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त है।

मर्यादित राय का आधार (Basis for Qualified Opinion):-

1. बैंक की प्राधिकृत अंश पूंजी रुपए 100 करोड़ है परंतु वित्तीय वर्ष 31.03.2025 के अंत में प्रदत्त अंश पूंजी रुपए 119.21 करोड़ है जो कि प्राधिकृत अंश पूंजी से अधिक है एवं नियमों के विरुद्ध है। बैंक को अपनी प्राधिकृत अंश पूंजी में वृद्धि के लिए आवश्यक कदम अति शीघ्र उठाना चाहिए।

2. लेखांकन नीतियों की अभिव्यक्ति AS-1 (DISCLOSURE OF ACCOUNTING POLICIES) की अपेक्षानुसार वित्तीय पत्रको को तैयार करने एवं उनके प्रस्तुत करने में अपनाई गई सभी महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सामान्यतः एक ही स्थान पर प्रस्तुत करना चाहिए एवं बोर्ड के द्वारा पारित किया जाना चाहिए

3. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक- 9 रेवेन्यू रेकॉग्नीशन के अनुसार, निवेश पर ब्याज आय को अर्जित आधार' (Accrual basis) के अनुसार प्रविष्टि किया जाना है, लेकिन बैंक ने नकद आधार (Cash Basis) के अनुसार इस तरह के आइटम जमा पर ब्याज आय की प्रविष्टि की है।

4. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-15 एम्प्लोगी बेनिफिट के अनुसार सुधाई गयी आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया है।

5. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-22 "एकाउंटिंग फॉर टैक्सेज ओन इनकम की आवश्यकता के अनुसार डैफर्ड टैक्स एसेट एवं लिएबिलिटीज़ के लिए प्रावधान नहीं किया गया है।

6. भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा निर्धारित लेखा मानक-29 प्रोविजन्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कंटिजेंटएसेट्स" की आवश्यकता के अनुसार कॅटिजेंट लायबिलिटीज नहीं दर्शाई गयी है।

7. "बोनस भुगतान अधिनियम 1965 की धारा 11 का पालन नहीं किया गया है।

8. **कैश रजिस्टर** और **तुलन पत्र** के अनुसार नकदी शेष में अंतर देखा गया है, जिसके लिए 31/03/2025 को दिए गए। विवरण नीचे दिए गए हैं।

क्र.	शाखा	कोड	तुलन पत्र के अनुसार शेष राशि	कैश रजिस्टर के अनुसार शेष राशि	अंतर्
1	एक्सटेंशन काउंटर मंडी आशठा	53	8,47,534.00	8,48,134.00	600.00

2	मंडी सीहोर	51	1,36,37,311.01	1,34,37,319.00	1,99,992.01
3	हेड ऑफिस	52	125.00	0.00	125.00

10. आयकर विभाग के फॉर्म 26 एस के अनुसार विभिन्न आय स्रातों पर टीडीएस रु.7,50,262.50 काटा गया है जबकि बैंक द्वारा पुस्तकों में रु. 7,14,889.27 दर्ज की गई है । जिसका विवरण निम्न अनुसार है:

Particulars	Amount
The New India Assurance Company Ltd	9,528.00
Central Bank Of India Regional Office	26,271.00
Agriculture Insurance Company Of India Limited	7,14,368.00
Pension Fund Regulatory And Development Authority Delhi	73.00
Sbi General Insurance Company Limited	22.50
Total	**7,50,262.50**
Less: As per books of accounts	7,14,889.27
Difference	**35,373.23**

11. प्रबंधन द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए आयकर के लिए प्रावधान बैंक के इनकम टैक्स ऑडिटर की वर्किंग के अनुरूप की गई है। गत वर्ष 2023-24 के सेल्फ असेसमेंट टैक्स Rs. 50,00,000 में से रिफंड Rs.5,44,370 को एडजस्ट करके लाभ हानि खाते में नाम किया गया है।

12. बैंक एवं इसकी समस्त 27 शाखाओं द्वारा स्थाई संपत्तियों का भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष 31 मार्च को किया जाता है तथा बैंक द्वारा इन सब स्थाई संपत्तियों पर डेप्रेसिअशन WDV मैथड के अनुसार लिया गया है। कंप्यूटर पर डेप्रेसिअशन WDV मैथड वैल्यू से 33.33% लिया गया हैं जबकि 33.33% एस एल एम् मेथड से लेना चाहिए था।

13. भारत सरकार से प्राप्य इंटरेस्ट सबवेंशन क्लेम को दर्ज नहीं किया गया है, इससे प्राप्त होने पर पुस्तकों में दर्ज किया जाता है।

अस्वीकरण राय का आधार(BASIS FOR DISCLAIMER OPINION)

1. **अपेक्स बैंक के निर्देशानुसार बैंक द्वारा PACS सदस्यों के PACS DMR खाते खोले जाने थे। बैंक द्वारा खाते खोले जाने की प्रक्रिया संस्था एवं बैंक स्तर पर जारी है जिसकी जांच की जाना अंकेक्षण के दौरान संभव नहीं है, अतः उक्त प्रक्रिया को शीघ्र अतिशिग्र पूर्ण कर उसका अवलोकन किया जावे।**

2. **बैंक द्वारा विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय बैंकों के साथ खाते रखे गए हैं इन बैंकों के पुस्तकीय शेष एवं तुलन पत्र के बैलेंस में काफी अंतर पाया गया है, साथ ही खातों के मिलान पत्रक बनाए गए हैं उनमे कई प्रविष्टियां वर्षों से लंबित है जिसकी जानकारी अप्राप्त है, जिसमे कुछ प्रविष्टियां चार्जेज एवं व्यक्तिगत खतों से लंबित है। जिन का समायोजन संभावित खतों में किया जाना आवश्यक था अतः इन असमायोजित प्रविष्टियों के करण संभावित आस्तियों एवं दायीत्वों व आय व्यय की राशियों को सही प्रदर्शित नहीं किया गया है। बैंक पत्रकों के मिलान नहीं किया जाने एवं असमायोजित प्रविष्टियों के पूर्ण विवरण के आभाव में वित्तीय विवरणियों पर प्रभाव का वर्तमान में सुनिश्चित करना संभव नहीं है।**

S. No.	Name of Bank	Balance as per Bank statement	Balance as per Books	Difference
1.	INDIAN OVERSEAS BANK	1,31,64,111.00	1,31,61,226.00	2,885.00
2.	STATE BANK OF INDIA	14,27,40,002.22	14,53,68,690.73	-26,28,688.51
3.	CENTRAL BANKOTHERS	11,64,43,314.86	10,95,16,470.92	69,26,843.94
4.	CENTRAL BANK FOR RTGS PURPOSE	5,64,01,514.95	5,66,01,514.95	-2,00,000.00
5.	ICICI(LPGCR)	8,20,68,602.68	39,75,46,225.60	31,54,77,622.92
6.	NOTIFIED BANKS 3 OTH	5,000.00	-	5,000.00
7.	NTFD BNK AXIS BANK OTH	3,05,80,386.10	3,26,90,990.23	-21,10,604.13
8.	NTFD BNK I C I CI BANK OTH	4,93,904.32	5,23,991.32	-30,087.00
9.	NTFD BNK I D B I BANK OTH	14,05,14,396.79	15,24,19,018.59	-1,19,04,621.80
10.	CSH BK AC APEX BK H O OTH	1,07,23,905.17	3,86,88,251.36	-2,79,64,346.19
11.	CSH BK AC APEX INDORE OTH	2,06,371.73	-	2,06,371.73
12.	CSH BK AC APX T T NAGER BR OTH	24,17,75,087.26	24,60,83,351.83	-43,08,264.57
13.	NOTIFIED BANKS 6 OTH	1,66,47,092.56	1,38,75,118.55	27,71,974.01
14.	NOTIFIED BANKS 7 OTH	1,07,03,525.21	1,26,48,693.61	-19,45,168.40

3. बैंक द्वारा NPA खातों का वर्गीकरण सबस्टैंडर्ड, डाउटफूल एवं लोस्स में सही नहीं किया गया है।

मर्यादित व अस्वीकरण राय (Qualified Opinion) :-

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार एवं प्रबंधन द्वारा हमें दी गयी जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, संस्था के वित्तीय विवरण, अंकेक्षण आपत्तियां, अंकेक्षण टिप में उल्लेखीत प्रधान कार्यालय और शाखाओं की अंनियमित्ताओं और खातों की टिपण्णी, अनुलग्न , LFAR लेखों पर टिप्पणियों और अस्वीकरण व मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलो के संभावित प्रभावों को छोड़कर वित्तीय विवरण सामान्यतः भारत में स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप सत्य और निष्पक्ष राय को दर्शाते हैं, परिवर्तनों के ज्ञापन (MOC) के साथ पढ़ें-

(अ) तुलना पत्र के मामले में, बैंक के कार्य की 31-03-2025 की स्थिति और

(ब) लाभ और हानि खाते के विवरण के मामले में, उस तारीख पर समाप्त होने वाले लाभ के लिए

अन्य मामले (Other Matters) :-

उपरोक्त मर्यादित राय के आधार में वर्णित मामलों के अलावा हम उपयोगकर्ताओं का ध्यान वित्तीय विवरण के अन्य मामलों पर आकर्षित करते हैं जो कि अनुलग्नक अ में उल्लेखित हैं। इन मामलों के सम्बन्ध में हमारी राय मर्यादित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट (Report on Other Legal and Regulatory Requirements) :-

1. हम सर्कुलर संख्या 106 DOS 192008 दिनांक 30-06-2008 विस्तृत पत्र संख्या NBDOSPOL/1309 / 1 / 2008-09 में दिए गए आदेश के अनुसार बैंक को श्रेणी अ में वर्गीकृत करते हैं।

2. उपर्युक्त दर्शायी गई लेखापरीक्षा की सीमा मर्यादित **व अस्वीकरण** राय **(Qualified Opinion & Disclaimer Opinion)** और हमारी लेखो पर कि गयी अन्य टिप्पणियों (Other Matters) जो कि लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ही भाग है के आधार पर हम सूचित करते हैं कि

(अ) हमने सभी जानकारियां और स्पष्टीकरण प्राप्त कर ली है जो कि लेखापरीक्षा के परीक्षण के लिए आवश्यक है।

(ब) हमारे द्वारा किये गए परीक्षण के अनुसार कानून द्वारा जरूरी खाते की उचित पुस्तकों को बैंक बना रही है।

(स) हम अपनी राय तथा सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के आधार पर प्रमाणित करते हैं कि, शाखा में कोई अनौपचारिक और अनियमितता नहीं है। यदि कोई भी अनौपचारिक और अनियमितता पायी गयी है, तो वह व्यक्तिगत शाखा की परिक्षण सूची में शामिल है।

3. बैंक ने वित्तीय विवरण में वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमेबाजी के प्रभाव का खुलासा किया है। (कृपया वित्तीय विवरण के लिए अनुलग्नक देखें।)

4. हम यह रिपोर्ट करते है कि, परीक्षण के दौरान हमने 27 शाखाओं का अंकेक्षण किया है। चूंकि बैंक ने प्रमुख बैंकिंग प्रणाली के लिए मुख्य रूप से कोर बैंकिंग सिस्टम का उपयोग किया है, इसलिए शाखाओं द्वारा वित्तीय रिटर्न जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है। तदनुसार हमारी लेखापरीक्षा मुख्य कार्यालय और केंद्रीय प्रक्रिया इकाई पर केन्द्रित की गयी है ताकि हमारे लिए उपलब्ध कराए गए परीक्षण के प्रयोजन के लिए जरूरी दस्तावेजों और जानकारी की आवश्यकता की पूर्ति हो।

दिनांक:-15.06.2025

वास्ते:- आर.सी.बाहेती एंड कंपनी
चार्टर्डअकाउंटेंट

रंजन बाहेती
(पार्टनर)

मेम्बरशिपन.:- 400993

UDIN :-

उन्नत कृषि से किसानों को अधिक मुनाफा : कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वर्णवाल

रबी वर्ष 2024-25 की समीक्षा और खरीफ 2025 की तैयारियों संबंधी बैठक सम्पन्न

भोपाल :कृषि उत्पादन आयुक्त श्री अशोक वर्णवाल ने कहा है कि प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में किसानों की आमदनी को दोगुना करने के लक्ष्य पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों को कृषि की उन्नत तकनीकें अपनाने, फसलों के विविधीकरण तथा खेती के साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि गतिविधियों के लिए प्रेरित किया जाए। सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और किसानों के खेत पर जाकर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वर्णवाल ने बुधवार को नर्मदा भवन में रबी वर्ष 2024-25 की समीक्षा और खरीफ 2025 की तैयारियों संबंधी भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग की संयुक्त बैठक ली। बैठक में प्रमुख सचिव उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण श्री अनुपम राजन, प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास श्री डी.पी.आहूजा, सचिव कृषि श्री एम.सेलवेन्द्रन, सचिव पशुपालन एवं डेयरी डॉ. सत्येन्द्र सिंह, संभागायुक्त भोपाल श्री संजीव सिंह, संभागायुक्त नर्मदापुरम श्री कृष्णगोपाल तिवारी आदि उपस्थित थे।

बैठक में बताया गया कि खरीफ 2024 में भोपाल जिले में एक लाख 7 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 28 हजार हेक्टेयर में धान, 8 हजार हेक्टेयर में मक्का तथा 1600 हेक्टेयर में अरहर बोई गई थी। इसी प्रकार रायसेन जिले में 58 हजार 932 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 2 लाख 74 हजार 547 हेक्टेयर में धान, 16 हजार 489 हेक्टेयर में मक्का तथा 15 हजार 193 हेक्टेयर में अरहर, विदिशा जिले में तीन लाख 82 हजार 250 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, एक लाख 2 हजार 528 हेक्टेयर में धान, 21 हजार 931 हेक्टेयर में मक्का, 7 हजार 526 हेक्टेयर में उड़द तथा 3 हजार 882 हेक्टेयर में ज्वार, राजगढ़ जिले में 4 लाख 36 हजार 742 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 28 हजार 301 हेक्टेयर में मक्का तथा सीहोर जिले में 3 लाख 20 हजार 920 हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन, 27 हजार हेक्टेयर में धान, 32 हजार हेक्टेयर में मक्का तथा एक हजार हेक्टेयर क्षेत्र में अरहर बोई गई थी। इस वर्ष धान के क्षेत्र में कमी तथा सोयाबीन और अरहर के क्षेत्र में वृद्धि की संभावना है।

कृषि उत्पादन आयुक्त श्री वर्णवाल ने कहा कि किसानों को बीज की उन्नत किस्में बोने के लिए प्रेरित किया जाए। बायोफोर्टिफाइड गेहूँ के बीज में आयरन और जिंक की मात्रा होती है जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। किसानों को गेहूँ के इस बीज की किस्म

एचआई 1650, 1636, 1633, 1655 बोने के लिए प्रेरित किया जाए। पूसा अरहर 16 अच्छी फसल है और इसका उत्पादन भी ज्यादा है। किसानों को फसलों के विविधीकरण के लिए प्रेरित करें।

श्री वर्णवाल ने कहा कि किसानों को प्रेशराइज्ड पाइप प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। खेत में पाइप लाइन डालने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जाता है। सभी जिलों में मृदा परीक्षण प्रयोग शालाएं कार्य कर रही हैं, इनके माध्यम से अधिक से अधिक मृदा परीक्षण करवाए जाएं। कस्टम हायरिंग केन्द्रों के माध्यम से किसानों को खेती के लिए उन्नत कृषि यंत्र एवं उपकरण भी उपलब्ध करवाए जाएं।

कृषि उत्पादन आयुक्त ने कहा कि किसानों को डीएपी उर्वरक के स्थान पर एनपीके उर्वरक इस्तेमाल करने की सलाह दी जाए। एनपीके में फसलों के लिए उपयोगी सभी पोषक तत्व होते हैं। उर्वरक वितरण के लिए डबल लॉक केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जाए तथा प्रयास किया जाए कि किसानों को लाइन में खड़ा न होना पड़े और उनके बैठने की अच्छी व्यवस्था की जाए।

श्री वर्णवाल ने कहा कि किसानों को समझाया जाए कि नरबाई जलाना खेत के लिए अत्यंत हानिकारक है। नरवाई जलाने के स्थान पर हैप्पीसीडर, सुपर सीडर से बुआई करने पर खेत को नुकसान नहीं होता, उसके पोषक तत्व बने रहते हैं तथा उत्पादकता अधिक आती है। जिन किसानों ने हैप्पी सीडर काउपयोग कर बुआई की उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले हैं, उन किसानों को रोल मॉडलों के रूप में प्रचारित करें।

शासन द्वारा ई मंडी प्रारंभ की गई है। किसानों को अपनी फसल बेचने में मंडियों में कम से कम समय लगना चाहिए। मंडियों को हाईटेक बनाने की कार्यवाही की जानी चाहिए। सरकार द्वारा फार्म गेट एप प्रारंभ किया गया है, इस पर किसान अपना पंजीयन कराके घर बैठे अपनी फसलें बेच सकता है।

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की समीक्षा के दौरान श्री वर्णवाल ने कहा कि मछली पालन में पारम्परिक व्यवसाय के स्थान पर उद्यम के माध्यम से केज कल्चर एवं बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी द्वारा उत्पादन लक्ष्य को 05 गुना किया जा सकता है। केजकल्चर द्वारा नये एंटरप्रेन्योर को मछली पालन से जोड़कर भोपाल जिले को मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। मत्स्य समितियों के सदस्यों के सहकारी बैंकों में खाते खुलवायें तथा सभी पात्र मछली पालकों को मछुआ किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ दें। जल संवर्धन अभियान के अंतर्गत संभाग के सभी जिलों में अमृत सरोवर, खेत तालाब को बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से मछली पालन के नये स्त्रोत के रूप में विकसित कर किसान को आर्थिक रूप से सशक्त कर सकते है।

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन

“योग: स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए संकल्प”

भोपाल, भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के पावन अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल मुख्यालय में आज एक भव्य, सुव्यवस्थित और प्रेरक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

इस वर्ष की थीम “योग फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट” रही, जो मानव स्वास्थ्य, संतुलित जीवनशैली और पर्यावरणीय जागरूकता के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

इस गरिमामयी अवसर पर संघ के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, उप प्रबंधक श्री गणेश प्रसाद मांझी, लेखा अधिकारी श्रीमती रेखा पिप्पल, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र की प्राचार्य श्रीमती मीनाक्षी बान, राज्य समन्वयक श्री संतोष येडे सहित संघ के सभी अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

हस्तशिल्प सेवा केंद्र, भोपाल के असिस्टेंट डायरेक्टर श्री नरसिंह सैनी अपने स्टाफ सहित विशेष रूप से कार्यक्रम में शामिल हुए।

संघ की विशेषज्ञ संस्था सीड (SEED) के सचिव श्री धर्मेंद्र राजपूत और उनकी टीम तथा CHCDS परियोजना के प्रशिक्षणार्थियों की सहभागिता ने आयोजन को और भी व्यापक बनाया।

योग प्रशिक्षण : सुश्री पूजा सिंह राजपूत द्वारा गहन अभ्यास और संवाद

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा प्रशिक्षित योग मास्टर सुश्री पूजा सिंह राजपूत का सजीव और अनुशासित योग सत्र।

उन्होंने उपस्थितजनों को ताड़ासन, त्रिकोणासन, वज्रासन, भुजंगासन, अनुलोम-विलोम, कपालभाति एवं ध्यान का अभ्यास करवाया और योग के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक लाभों की विस्तृत जानकारी दी।

उनका स्पष्ट संदेश था कि:

● “योग केवल व्यायाम नहीं, बल्कि एक जीवनशैली है जो शरीर, मन और आत्मा के बीच समरसता स्थापित करती है। यह स्वास्थ्य की कुंजी और आंतरिक ऊर्जा का स्रोत है।”

योग संकल्प और प्रेरक नेतृत्व के विचार

कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को “योग फॉर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट” की संकल्प शपथ दिलाई गई, जिसमें दैनिक योग अभ्यास, स्वास्थ्य के प्रति प्रतिबद्धता, समाज में जागरूकता लाना और पर्यावरणीय संतुलन हेतु कार्य करने के संकल्प लिए गए।

असिस्टेंट डायरेक्टर श्री नरसिंह सैनी (हस्तशिल्प सेवा केंद्र, भोपाल) ने अपने वक्तव्य में कहा:

● “योग हमारे कार्य और जीवन के बीच संतुलन बनाने का सशक्त माध्यम है। सहकारी और सरकारी संस्थानों में कार्यरत कर्मियों के लिए यह तनाव प्रबंधन और सकारात्मक सोच का आधार बन सकता है।”

इस अवसर पर महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने अपने विचार साझा करते हुए कहा:

● “योग केवल एक दिवस का आयोजन नहीं, बल्कि यह जीवन का अनुशासन है। यह हमारे भीतर सेवा, समर्पण, धैर्य और मानसिक स्थिरता को जाग्रत करता है। सहकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हम सभी के लिए यह न केवल आत्मिक शांति, बल्कि सामूहिक कार्यकुशलता और कार्यस्थल की ऊर्जा बढ़ाने का आधार बन सकता है। जब हम योग को जीवनशैली बनाते हैं, तो व्यक्तिगत विकास के साथ संस्था भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचती है।”

“सहकार से समृद्धि” व्यवसाय विविधीकरण पर कार्यशाला आयोजित

भोपाल, भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की महत्वाकांक्षी योजना”सहकार से समृद्धि”के अंतर्गत अपेक्स बैंक मुख्यालय, भोपाल में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। यह कार्यशालाजिला सहकारी बैंकों से सम्बद्ध बहुदेशीय सहकारी समितियों में व्यवसाय केविविधीकरणको प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

कार्यशाला कोअपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ताने संबोधित करते हुए सहकारी क्षेत्र में व्यवसाय की बहुविध संभावनाओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि बदलते समय में सहकारी समितियों को केवल पारंपरिक कृषि ऋणों तक सीमित न रहकर विपणन, प्रसंस्करण, भंडारण, दुग्ध, मुर्गीपालन, बीज उत्पादन, कृषि यंत्र किराया आदि क्षेत्रों में भी अपनी भागीदारी बढ़ानी होगी। श्री गुप्ता ने योजनान्तर्गत राज्य में क्रियान्वित संभावित गतिविधियों की रूपरेखा एवं वित्तीय सहयोग की संभावनाओं पर भी विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर बैंक कीवि.क.अ. (वित्त एवं क्रेडिट अधिकारी) श्रीमतीअरुणा दुबे, श्रीअरुण मिश्र, श्रीसंजय मोहन भटनागर, श्रीमतीकृति सक्सेना, उप महाप्रबंधकश्रीके.टी. सज्जन, वि.क.अ. श्रीअरविन्द बौद्धएवं श्रीआर.सी. पटलेसहित बैंक के अनेकवरिष्ठ अधिकारीगणएवं विभिन्नसहकारी समितियों के प्रबंधकभी उपस्थित थे।

कार्यशाला में बहुदेशीय सहकारी समितियों के सशक्तिकरण, वित्तीय उत्पादों में नवाचार, किसानों एवं ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने की रणनीतियों तथा “सहकारिता से गांव की समृद्धि” के विज़न पर भी चर्चा हुई।कार्यक्रम के अंत में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा योजना को सफलतापूर्वक लागू करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण, मार्गदर्शन एवं वित्तीय सहायता की आवश्यकता पर सुझाव प्रस्तुत किए गए। कार्यशाला ने सहकारी क्षेत्र के लिए एक नई ऊर्जा एवं दिशा प्रदान की।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।